भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न सं.29
02/02/2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जोशीमठ में जमीन धंसना

29. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के कारणों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों के किसी समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समूह को क्या अधिदेश दिया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास हिमालयी क्षेत्र के किसी अन्य भाग से भू-धंसाव की कोई रिपोर्ट है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस आपदा को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (च) आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार, जहां भी आवश्यक हो, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए उपयुक्त तैयारी, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने के लिएदेश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र क्रमश: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) हैं।

हिमालय के अनेकभाग अस्थिर हैं और इनमें गतिशील भूविज्ञान है, जिसके कारण धंसाव और भूस्खलन होता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इन क्षेत्रों के भूस्खलन मानचित्र तैयार किए हैं।

उत्तराखंड राज्य सरकार ने विभिन्न अनुसंधान संस्थानोंजैसे (i) राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद, (ii) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीआईएस), कोलकाता, (iii) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी), देहरादून, (iv) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की, (v) केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), फरीदाबाद, (vi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रुड़की, (vii) भारतीय रिमोट सेंसिंगसंस्थान (आईआईआरएस), देहरादून और (viii) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़कीके विशेषज्ञों को अलग-अलग कार्य सौंपे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भी उन्हें तकनीकी दिशानिर्देशप्रदान कर रहा है।

विशेषज्ञों के इस समूह का कार्य स्थिति और इससे जुडे नुकसान का तत्काल आकलन करना तथा इसके कारणों और सहायक कारकों का अध्ययन करना है।

जोशीमठ क्षेत्र में भू-धंसाव के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

*****